



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3259]

नई दिल्ली, बधुवार, नवम्बर 22, 2017/अग्रहायण 1, 1939

No. 3259]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 2017/AGRAHAYANA 1, 1939

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2017

का.अ. 3713(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश साधारण जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

आदेश

26 अक्तूबर, 2017

श्री राम बिहारी पांडे (जिसे इसमें इसके पश्चात् “याची” कहा गया है) ने तारीख 8 मार्च, 2017 की एक याचिका यह कथन करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को संबोधित की है कि श्रीमती रीती पाठक, 11-सीधी, जिला सीधी, मध्य प्रदेशसे संसद् सदस्य (लोक सभा) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्रत्यर्थी” कहा गया है), भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 एवं अनुच्छेद 103 के अधीन निरर्हित हो गई हैं ;

और याची ने यह अभिकथन किया है कि प्रत्यर्थी ने वर्ष 2014 के साधारण निर्वाचनों को लड़ने के लिए अपना नामनिर्देशन भरा और 16 मई, 2014 को अपने निर्वाचित किए जाने की तारीख को वह अध्यक्ष, जिला पंचायत, जिला सीधी (मध्य प्रदेश) का पद धारण कर रही थी, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन “लाभ का पद” है। उक्त निर्वाचनों का परिणाम 16 मई, 2014 को घोषित किया गया था और उसी तारीख को प्रत्यर्थी को निर्वाचित घोषित किया गया था। प्रत्यर्थी ने तत्पश्चात् 24 मई, 2014 को जिला पंचायत के अध्यक्ष पद से अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया, जिसे 29 मई, 2014 को स्वीकार कर लिया गया था। घटनाओं की यह श्रृंखला स्पष्ट रूप से यह साबित करती है कि चूंकि प्रत्यर्थी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने निर्वाचन की तारीख को लाभ के पद पर थी, अतः, वह संसद् का सदस्य होने के लिए निरर्हित है ;

और उक्त याचिका को भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन यथा अपेक्षित रूप से भारत निर्वाचन आयोग की राय के लिए निर्दिष्ट किया गया था;

और भारत निर्वाचन आयोग ने मामले की जांच की और यह कथन किया है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 32(5) के अनुसार, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष संसद् सदस्य बन जाता है तो उसके स्थान को अध्यक्ष के रूप में उसके ऐसा सदस्य बनने की तारीख से रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा। इस रीति में प्रत्यर्थी निर्वाचन के पश्चात् जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद कभी भी धारण नहीं कर रही थी;

और अनुच्छेद 103 के अधीन राष्ट्रपति की संसद् किसी के आसीन सदस्य की निरर्हता के प्रश्न का विनिश्चय करने की अधिकारिता केवल तभी उद्भूत होती है, जब निरर्हता संसद् सदस्य का निर्वाचन होने के पश्चात् उपगत की जाती है। भारत निर्वाचन आयोग बनाम साका वेंकटा सुब्बा राव, एआईआर 1953 एससी 210 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि निर्वाचन आयोग की अनुच्छेद 103 एवं अनुच्छेद 192 के अधीन किसी सदस्य की निरर्हता के मामले में जांच करने की अधिकारिता केवल उन निरर्हताओं के लिए लागू है, जिनके अधीन कोई संसद् सदस्य या विधान सभा का सदस्य ऐसा सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात् हो जाता है ;

और भारत निर्वाचन आयोग ने याचिका की जांच करने के पश्चात्, 31 जुलाई, 2017 को यह मत देते हुए अपनी राय दी है कि श्रीमती रीती पाठक ने मध्य प्रदेश पंचायती राज एवम ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 32 को ध्यान में रखते हुए लाभ का पद धारण करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन कोई निरर्हता उपगत नहीं की है। भारत निर्वाचन आयोग की राय की एक प्रति इसके साथ उपाबद्ध है ;

अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभिव्यक्त राय के आलोक में मामले पर विचार करने के पश्चात्, मैं राम नाथ कोविंद, भारत का राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन, मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अभिनिर्धारित करता हूं कि श्री राम बिहारी पांडे द्वारा श्रीमती रीती पाठक, संसद् सदस्य (लोक सभा), मध्य प्रदेश की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर फाइल की गई तारीख 8 मार्च, 2017 की याचिका चलाए जाने योग्य नहीं है।

भारत का राष्ट्रपति

राष्ट्रपति के आदेश का उपाबंध

निर्वाचन सदन

भारत निर्वाचन आयोग

अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

संदर्भ मामला सं. 2015 का 6(पी)

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के अधीन

भारत के राष्ट्रपति से संदर्भ)

संदर्भ : संदर्भ मामला संख्या 2015 का 6(पी)-भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के अधीन श्रीमती रीती पाठक, संसद् सदस्य लोक सभा की निरर्हता के लिए आयोग का मत लेने हेतु भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त संदर्भ - तत्संबंधी।

राय

भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त यह संदर्भ दिनांक 10 मई, 2017 है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की इस प्रश्न पर राय मांगी गई है कि क्या मध्य प्रदेश के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 11-सीधी, जिला-सीधी से संसद सदस्य (लोक सभा) श्रीमती रीति पाठक “लाभ का पद” धारण करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन निरर्हता के अध्यधीन हो गई हैं।

2. उक्त संदर्भ में निरर्हता का प्रश्न, श्री रामबिहारी पाण्डेय (इसमें इसके पश्चात “याचिकाकर्ता”) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के समक्ष दाखिल याचिका दिनांक 08 मार्च, 2017 के कारण उत्पन्न हुआ, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता ने श्रीमती रीति पाठक (इसमें इसके बाद “प्रत्यर्थी”) की “लाभ का पद” धारण करने के आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1) (क) के अध्यधीन निरर्हता की मांग की है।

मामले के तथ्य

3. उक्त याचिका में इस मामले के अनावृत तथ्य निम्नलिखित अनुसार हैं:

4. प्रत्यर्थी को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्ष 2014 के साधारण निर्वाचन में निर्वाचित घोषित किया गया था। वर्ष 2014 के संसदीय निर्वाचनों में लड़ने हेतु अपना नाम-निर्देशन पत्र भरते समय तथा उनको निर्वाचित घोषित किए जाने की तारीख को, वे जिला पंचायत, जिला सीधी (मध्य प्रदेश) के अध्यक्ष का पद धारण कर रही थीं, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन “लाभ का पद” है।

5. उक्त निर्वाचनों के परिणाम दिनांक 16 मई, 2014 को घोषित किए गए थे और उसी दिन प्रत्यर्थी को निर्वाचित घोषित किया गया था। इसके बाद प्रत्यर्थी ने दिनांक 24 मई, 2014 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था जिसे दिनांक 29 मई, 2014 को स्वीकार कर लिया गया था। ये घटनाक्रम स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करते हैं कि चूंकि प्रत्यर्थी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन की तारीख को लाभ का पद धारण कर रही थीं और इसलिए वे संसद का सदस्य होने के लिए निरर्हित हो जाती हैं।

शामिल विवादयक

6. आयोग ने रिकार्ड पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक जांच की है। सुसंगत दस्तावेजों तथा राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त याचिका में किए गए निवेदनों की जांच और उनका विश्लेषण करने के पश्चात, कोई राय बनाने के लिए निम्नलिखित विवादयक निर्धारित किए जाने आवश्यक हैं:

क) क्या प्रत्यर्थी द्वारा सीधी की जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में धारण किया गया पद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के अधीन निरर्हता आकर्षित करने के लिए उन्हें लाभ के पद को धारण करने वाला व्यक्ति बनाता है?

निवेदनों का विश्लेषण और भारत निर्वाचन आयोग का निष्कर्ष

7. याची द्वारा रिकार्ड पर रखे गए दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद को धारण किए हुए रही हैं। जिला पंचायत का गठन और उसकी स्थापना मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 10(3) के अधीन हुई है और अध्यक्ष इस अधिनियम की धारा 32 के अनुसार निर्वाचित होता है। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 स्पष्ट रूप से यह उपबंधित करता है कि यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष संसद सदस्य बन जाता है तो अध्यक्ष पद के रूप में उसकी

सीट इस प्रकार से सदस्य बनने की तारीख से रिक्त मानी जाएगी। सुविधा के लिए, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 32(5) को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है:-

32. जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन-

(5) यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संसद के किसी सदन का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य या किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बन जाता है तो उसके द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, का पद उस तारीख से रिक्त किया हुआ माना जाएगा जब से वह ऐसा सदस्य या चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बन जाता है और धारा 38 के प्रयोजनार्थ ऐसे पद की आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई मानी जाएगी।

इस उपबंध का केवल अवलोकन ही यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि चूंकि उपबंध स्वयं ही पद के रिक्त होने को मानता है इसलिए प्रत्यर्थी द्वारा 24 मई, 2014 को त्याग-पत्र देने और 29 मई, 2014 को उसे स्वीकार कर लिए जाने का कोई महत्व नहीं है। विधि में स्थापित इस प्रकार की स्थिति से यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यर्थी ने संसद सदस्य चुने जाने की तारीख अर्थात् 16 मई, 2014 से उक्त पद से मुक्ति पा ली थी जो कि उनके स्वैच्छिक त्यागपत्र की तारीख से पहले की तारीख थी। इस प्रकार से प्रत्यर्थी निर्वाचन के बाद से जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद की धारक नहीं थीं।

8. हालांकि, मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 32 पर विचार किए बिना केवल तर्क करने की दृष्टि से भी अगर यह मान लिया जाता है कि प्रत्यर्थी ने अपने निर्वाचन के बाद 13 दिन की अवधि के लिए अर्थात् 29 मई 2015 तक, जब उनका त्यागपत्र स्वीकृत किया गया था, जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में पद को धारण किया था, तो भी ऐसे पद से उत्पन्न होने वाली निरर्हता के प्रश्न पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। विधि का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि अनुच्छेद 103 के अंतर्गत संसद के आसीन सदस्य की निरर्हता के प्रश्न पर निर्णय लेने की राष्ट्रपति की अधिकारिता केवल तब उत्पन्न होती है जब निरर्हता संसद के एक सदस्य के रूप में निर्वाचन के उपरांत ग्रस्त हुई हो। निर्वाचन आयोग, भारत बनाम सका वेंकट सुब्बा राव, एआईआर 1953 एससी 210 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्राधिकारपूर्वक निर्धारित किया गया है कि निर्वाचन आयोग के पास उस निरर्हता की जांच करने की अधिकारिता है जो सदस्य के निर्वाचन के बाद उत्पन्न हुई हो। अनुच्छेद 103 और अनुच्छेद 192 केवल ऐसी निरर्हताओं पर लागू हैं जिनके प्रति संसद के सदस्य या विधान सभा के सदस्य, उनके ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के उपरांत अधीन हो जाते हैं और न तो राष्ट्रपति और न ही निर्वाचन आयोग के पास इस बात की अधिकारिता है कि वे ऐसी निरर्हता की जांच करें जो सदस्य के रूप में निर्वाचित होने से पहले उत्पन्न हुई हो। उक्त निर्णय का संगत पैरा यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है :

“17हमारी राय में ये दोनों अनुच्छेद एक साथ काम करते हैं और उस परिस्थिति में उपचार उपलब्ध कराते हैं जब कोई सदस्य, सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद निरर्हता ग्रसित करता है। न केवल अनुच्छेद 190(3) में शब्द “ग्रस्त हो जाता है” और अनुच्छेद 192(1) में “ग्रस्त हो गया है” सदस्य के निर्वाचित होने के बाद उसकी स्थिति में परिवर्तन को निर्दिष्ट करता है बल्कि यह उपबंध कि तदुपरि उसके स्थान को रिक्त हो जाना है यानि वह स्थान जो सदस्य उस से पहले भरे हुए था, उसके निरर्हित होने पर रिक्त हो जाता है, आगे इस राय को और अधिक प्रबल बनाता है कि अनुच्छेद केवल ऐसे आसीन सदस्य का अनुद्धान करता है जो इस तरह आसीन बने रहने के समय निरर्हता से ग्रसित होता है। यह सुझाव कि अनुच्छेद 190(3) में प्रयुक्त भाषा एक पूर्व-विद्यमान निरर्हता पर समान रूप से लागू की जा सकती है क्योंकि एक सदस्य से उस क्षण अपना स्थान खाली करने की अपेक्षा की जाती है जब वह निर्वाचित हो, एक अस्वाभाविक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण अर्थान्वयन है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है (बल दिया

जाता है)। अटार्नी जनरल ने स्वीकार किया कि यदि शब्द “है” को “हो जाता है”; या “हो गया है” से प्रतिस्थापित कर दिया गया होता तो यह उनके द्वारा जिस प्रकार के अर्थ के लिए तर्क दिया जा रहा है उसको अधिक उपयुक्त तरीके से सम्प्रेषित करता लेकिन वह यह बताने में असमर्थ रहे कि उसका प्रयोग क्यों नहीं किया गया।”

ब्रुंदाबन नायक बनाम भारत निर्वाचन एवं अन्य एआईआर 1965 एससी 1892 के और एक मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा समरूप दृष्टिकोण अपनाया गया था जिसमें सका वेंकट राव (ऊपर) के निर्णय के अंतर्गत निर्धारित अनुपात का संदर्भ देते हुए न्यायालय ने कहा कि वह निरर्हता, जिसका अनुच्छेद 191(1) में संदर्भ दिया गया है, सदस्य के निर्वाचन के उपरांत ही ग्रसित की जानी चाहिए। संगत पैरा निम्नलिखित के अनुसार है :

“7.....यह सुस्थापित है कि वह निरर्हता, जिसका अनुच्छेद 191(1) में संदर्भ दिया गया है, अवश्यतया सदस्य के निर्वाचन के बाद ग्रसित की जाए। यह निष्कर्ष अनुच्छेद 190(3)(क) के उपबंधों से निकलता है। यह अनुच्छेद विधिवत् रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा स्थानों को खाली करने से संबंधित है। उप-अनुच्छेद (3)(क) में उपबंध किया गया है कि यदि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में उल्लिखित किन्हीं निरर्हताओं से ग्रसित हो जाता है तो उसका स्थान तदुपरि रिक्त हो जाएगा। प्रसंगवश, हम यह भी कहना चाहेंगे कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित संगत उपबंध संविधान के अनुच्छेद 101, 102 और 103 द्वारा विहित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग, भारत बनाम सका वेंकट सुब्बा राव एवं भारत संघ-मध्यवर्ती में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 190(3) और 192(1) केवल उन्हीं निरर्हताओं पर लागू हैं जिनसे कोई सदस्य, सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के उपरांत ग्रसित हो जाता है।”

9. तदनुसार, निर्वाचन आयोग का यह अभिमत है कि यदि लाभ के पद की धारक होने के नाते प्रत्यर्थी के विरुद्ध याचिका में लगाए गए आरोपों को तथ्यात्मक रूप से सही मान भी लिया जाए तो भी अनुच्छेद 103 के निबंधनों के अनुसार इस बात का कोई प्रश्न नहीं उठता है कि क्या श्रीमती रीति पाठक अपने निर्वाचन के उपरांत निरर्हता से ग्रसित हो गई हैं। इसलिए, वर्तमान संदर्भ संविधान के अनुच्छेद 103 के अंतर्गत पोषणीय नहीं है।

निष्कर्ष

10. ऊपर जिस तथ्यात्मक एवं विधिक अंश का विश्लेषण किया गया है उसे ध्यान में रखते हुए भारत के माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त संदर्भ दिनांक 10 मई, 2017 पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 एवं 103 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग का अभिमत यह है कि श्रीमती रीति पाठक ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 32 के दृष्टिगत लाभ के पद की धारक होने के नाते किसी निरर्हता से ग्रस्त नहीं हुई हैं।

11. तदनुसार, भारत निर्वाचन आयोग का, उपर्युक्त आशय का अभिमत एतद्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रदान किया जाता है।

ओ.पी.रावत

(निर्वाचन आयुक्त)

ए.के.जोति

(मुख्य निर्वाचन आयुक्त)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 31.07.2017

[फा. सं. एच- 11026/04/2017-वि.2]

डॉ. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd November, 2017

S.O. 3713(E).—The following Order made by the President is published for general information:-**ORDER**26th October, 2017

Whereas Shri Rambihaari Pandey (hereinafter the “Petitioner”) has addressed a petition dated the March 08, 2017 to the undersigned alleging that Smt. Riti Pathak, Member of Parliament (Lok Sabha) (hereinafter the “respondent”), from the parliamentary constituency of 11-Sidhi, District Sidhi, Madhya Pradesh has become subject to disqualification under Article 102 & 103 of the Constitution of India.

And whereas the Petitioner has alleged that the respondent filed her nomination for contesting the general elections of 2014 and on the date of her being elected on 16th May, 2014, she was holding the office of President of Zila Panchayat, District Sidhi (M.P.) which is an “office of profit” under article 102 of the Constitution of India. The result of said elections was announced on 16th May, 2014 and on the same date the respondent was declared to be elected. The respondent subsequently submitted her resignation from the post of President Zila Panchayat on 24th May, 2014 which was accepted on 29th May, 2014. These chains of events clearly establish that since the respondent was occupying the office of profit on the date of her election to the Parliamentary constituency, she thus stands disqualified for being the Member of the Parliament;

And whereas the said petition was referred to the Election Commission of India seeking its opinion as required under article 103 of the Constitution of India;

And whereas, under article 103 the jurisdiction of the President to decide question of disqualification of a sitting Member of the Parliament arises only if disqualification is incurred after election as a Member of the Parliament. In Election Commission of India v/s Saka Venkata Subba Rao, AIR 1953 SC 210 the Supreme Court of India held that Election Commission jurisdiction to enquire into case of disqualification of a member under articles 103 & 192 is applicable only to disqualifications to which a Member of the Parliament or Member of Legislative Assembly becomes subject after he is elected as such member;

And whereas the Election Commission of India, after examining the petition, has given its opinion on July 31, 2017, opining, that Smt. Riti Pathak has not incurred any disqualification under article 102 of the Constitution of India for being a holder of office of profit in view of section 32 of Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993. A copy of the opinion of Election Commission of India;

Now, therefore, having considered the matter in the light of the opinion expressed by the Election Commission of India, I Ram Nath Kovind, President of India, in exercise of the powers conferred upon me under article 103 of the Constitution of India, do hereby

hold that the petition dated March 08, 2017, filed by Shri Rambihaari Pandey, on the question of alleged disqualification of Smt. Riti Pathak, Member of Parliament (Lok Sabha), Madhya Pradesh, is not maintainable.

President of India

ANNEXURE TO THE ORDER OF THE PRESIDENT**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

NIRVACHAN SADAN

ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

REFERENCE CASE NO. 6(P) OF 2015**[Reference from the President of India under Art. 102 and 103 of the Constitution of India]**

In re: Reference Case No. 6(P) Of 2015- Reference received from the President of India for the opinion of the Commission for the disqualification of Smt. Rithi Pathak, Member of Parliament (Lok Sabha) under Articles 102 & 103 of the Constitution of India - regarding

OPINION

This is a reference dated 10th May 2017, received from the President of India seeking opinion of the Election Commission of India under Article 103 of the Constitution of India, on the question whether Smt. Rithi Pathak, a Member of Parliament (Lok Sabha) from the parliamentary constituency of 11- Sidhi, District Sidhi, Madhya Pradesh has become subject to disqualification, under Article 102 of the Constitution of India for holding an “office of profit”.

2. In the said reference, the question of disqualification arose because of a petition dated 08th March 2017, filed by Shri. Rambihaari Pandey (hereinafter the “*Petitioner*”) before the President of India, whereby the petitioner has sought disqualification of Smt. Rithi Pathak (hereinafter the “*Respondent*”) under Article 102 (1) (a) of the Constitution of India on the ground of “office of profit”.

Facts of the case

3. The facts of the case, as disclosed in the said petition, are as follows:

4. The Respondent was elected in the general elections of 2014 on the ticket of the Bharatiya Janata Party. At the time of filing her nomination for contesting the Parliamentary elections of 2014 and on the date of her being elected she was holding the office of President of Zila Panchayat, District Sidhi (M.P.) which is an “office of profit” under article 102 of the Constitution of India.

5. The results of the said elections were announced on 16th May 2014 and on the same date the Respondent was declared to be elected. The Respondent subsequently submitted her resignation from the post on 24th May 2014 which was accepted on 29th May 2014. These chains of events clearly establish since the Respondent was occupying the office of profit on the date of her election to the Parliamentary constituency and thus stands disqualified for being the member of the Parliament.

Issues involved

6. The Commission has carefully examined all documents on record. After examining and analysing the relevant documents and the submissions made in the petition received by the President, the following issue needs to be determined in order to arrive at an opinion:

- a) Whether the holding of the post as the President of the Zila Panchayat, Sidhi by the Respondent makes her a holder of office of profit under Articles 102 and 103 of the Constitution of India in order to attract disqualification?

Analysis of the submissions and findings of the Election Commission of India

7. The perusal of the documents placed on record by the petitioner shows that the Respondent in the instant matter has been holding the office as the President of Zila Panchayat since. The Zila Panchayat has been formed and established under Section 10(3) of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 and the President is elected according to the Section 32 of the Act. According to Section 32 (5) of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 clearly provides that if a President of the Zila Panchayat becomes a Member of Parliament, his seat shall be deemed to have been vacated as President w.e.f. the date of his becoming such Member. For the sake of convenience the Section 32 (5) of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 is reproduced here below:

32. Election of President and Vice-President of Zila Panchayat-

(5) If a President or a Vice-President of Zila Panchayat becomes a member of either House of Parliament or a member of the State Legislative Assembly or a Chairman or Vice-Chairman of a Co-operative Society, he shall be deemed to have vacated his office as President or Vice-President, as the case may be, with effect from the date of his becoming such member or Chairman or Vice-Chairman and a casual vacancy shall be deemed to have occurred in such office for the purpose of Section 38.

A bare perusal of this provision clearly shows that, as the provision itself provides for the deemed vacation of office, tendering of resignation by the Respondent on 24th May 2014 and its further acceptance on the 29th May

2014 holds no significance. By this established position in law it becomes sufficiently clear that the Respondent was absolved from the said post on the date she got elected as the Member of the Parliament i.e. on 16th May 2014 which is prior to the date of her voluntary resignation. In this manner the Respondent after the election was never the holder of the office of President of the Zila Panchayat.

8. Although, even for the sake argument without taking into consideration the Section 32 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 if it is assumed that the Respondent held the office as the President of Zila Panchayat for a period of 13 days after her election i.e. till 29th May 2015 when her resignation was accepted, the question of disqualification arising out of such an office cannot be decided. It is a well settled principle of law that under Article 103 the jurisdiction of the President to decide question of disqualification of a sitting member of the Parliament arises only if disqualification is incurred after-election as a member of the Parliament. It has been authoritatively laid down by the Supreme Court in the case of *Election Commission, India v. Saka Venkata Subba Rao*, AIR 1953 SC 210 that Election Commission has the jurisdiction to enquire into a disqualification which arose after the member's election. Article 103 and Article 192 are applicable only to disqualifications to which a member of the Parliament or member of Legislative Assembly becomes subject after he is elected as such member and neither the President nor the Election Commission have the jurisdiction to enquire into a disqualification which arose prior to getting elected as a Member. The relevant paragraph of the said judgement is reproduced here below:

"17In our opinion these two articles go together and provide a remedy when a member incurs a disqualification after he is elected as a member. Not only do the words "becomes subject" in article 190(3) and "has become subject" in article 192 (1) indicate a change in the position of the member after he was elected, but the provision that his seat is to become thereupon vacant, that is to say, the seat which the member was filling theretofore becomes vacant on his becoming disqualified, further reinforces the view that the article contemplates only a sitting member incurring the disability while so sitting. The suggestion that the language used in article 190(3) can equally be applied to a pre-existing disqualification as a member can be supposed to vacate his seat the moment he is elected is a strained and farfetched construction and cannot be accepted (emphasis added). The Attorney-General admitted that if the word "is" were substituted for "becomes"; or "has become", it would more appropriately convey the meaning contended for by him, but he was unable to say why it was not used."

A similar view was taken by the Supreme Court in another case of *Brundaban Nayak v. Election Commission of India and Anr.* AIR 1965 SC 1892 where the Court while referring to the ratio laid under the judgement of *Saka Venkata Rao (supra)* said that the disqualification, to which Article 191(1) refers, must be incurred subsequent to the election of the member. The relevant paragraph is as thus:

"7....It is well-settled that the disqualification to which Art. 191(1) refers, must be incurred subsequent to the election of the member. This conclusion follows from the provisions of Art. 190(3)(a). This Article refers to the vacation of seats by members duly elected. Sub-Article (3)(a) provides that if a member of a House of the Legislature of a State becomes subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of Art. 191, his seat shall thereupon become vacant. Incidentally, we may add that corresponding provisions with regard to the disqualification of members of both Houses of Parliament are prescribed by Articles 101, 102 and 103 of the Constitution. It has been held by this Court in Election Commission, India v. Saka Venkata Subba Rao and Union of India - Intervener/that Articles 190(3) and 192(1) are applicable only to disqualifications to which a member becomes subject after being elected as such."

9. The Election Commission is accordingly of the opinion that even if the allegations made in the petition against the Respondent for being a holder of office of profit are presumed to be factually correct, no question arises in terms of article 103 as to whether Smt. Rithi Pathak has become subject to a disqualification after her election. Hence, the present reference is not maintainable under Article 103 of the Constitution.

Conclusion

10. Taking into account the factual and Legal portion analysed above, the opinion of Election Commission of India under Article 102 and 103 of the Constitution of India on the reference dated 10th May 2017 received from the Hon'ble President of India is that Smt. Rithi Pathak has not incurred any

disqualification for being a holder of office of profit in view of Section 32 Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993.

11. Accordingly, the opinion of the Election Commission of India is hereby tendered to the President of India to the above effect under Article 103 of the Constitution of India.

O.P.Rawat

(Election Commissioner)

Place: New Delhi

Date: 31.07.2017

A.K.Joti

(Chief Election Commissioner)

[F.No.H-11026/4/2017-Leg.II]

Dr. REETA VASHISTHA, Addl. Secy.